



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 13 अप्रैल, 2023 ई०

चैत्र 23, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-03

संख्या 243/XVIII(03)/2023-02(01)/2016 T.C.

देहरादून, 13 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प० आ०-34

राज्यपाल अधिसूचना सं०-98/XVIII(03)/2016-20(01)/2014 दिनांक 09.02.2016 के द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 51 (1) के अधीन गठित भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण को निरस्त करते हुए, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" (केन्द्रीय अधिनियम सं०-30 वर्ष 2013) की धारा 51 संपठित धारा 52 एवं 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जिले में "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" स्थापित करने और उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मा० मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से वर्तमान समस्त जिला न्यायाधीशों अथवा जिला न्यायाधीशों द्वारा नामित अपर जिला न्यायाधीशों को उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त प्रभार के रूप में अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए "पीठासीन अधिकारी" अधिसूचित करती है तथा वह उक्त अधिनियम की धारा 64 के अधीन उन्हें दिये गये निर्देशों या धारा 64 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन आवेदक द्वारा किये गये आवेदनों को ग्रहण करने तथा विनिश्चय करने की अधिकारिता का भी प्रयोग करेंगे।

आज्ञा से,

सचिन कुर्वे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 243/XVIII(3)/2023-02(01)/2016 T.C. dated April 13, 2023 for general information:

No. 243/XVIII(3)/2023-02(01)/2016 T.C.

Dated Dehradun, April 13, 2023

NOTIFICATION

The Governor is pleased to repeal the Land Acquisition Rehabilitation Authority constituted vide Notification No-98/XVIII(3)/2016-20(01)/2014 dated 09-02-2016, under Section 51 (1) of the "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" and by exercising the powers conferred by section 51 read with section 52 and 53 of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" (Central Act No. -30, Year 2013), is pleased to establish the "Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Authority" in each district of the State of Uttarakhand and to notify all the existing District Judges or Additional District Judges nominated by the District Judge concerned as the "Presiding Officers," in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, to the exercise the power of the the Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Authority within their respective territorial jurisdiction, in addition to their existing work and they shall also exercise jurisdiction for entertaining and deciding the references made to it under section 64 or applications made by the applicant under second proviso to sub-section (1) of section 64 of the aforesaid Act.

By Order,

SACHIN KURVE,
Secretary, Revenue